दैनिक हिन्दुस्तान
10-04-2009

धरना दिया

अपनी मांगों के समर्थन में एमटीएनएल के अधिकारियों ने गुरुवार को जीवन भारती बिल्डिंग के बाहर धरना दिया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि एमटीएनएल प्रबंधन ने जल्दी ही सरकार द्वारा निर्धारित नया वेतनमान 30 प्रतिशत फिटमेंट के साथ लागू नहीं किया तो सभी अधिकारी 15 अप्रैल से प्रबंध निदेशक कार्यालय पर क्रमिक अनशन पर बैठ जाएंगे।

वीर अर्जुन
10-04-2009

मांगों को लेकर एमटीएनएल अधिकारियों ने दिया धरना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल (देशबन्धु)। एमटीएनएल प्रबंधन के खिलाफ गुरुवार को ज्वाइंट फोरम ऑफ एक्जीक्यूटिव्स एसोसिएशन ऑफ एमटीएनएल के बैनर तले जीवन भारती बिल्डिंग पर एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। जॉइंट फोरम ऑफ एक्जीक्यूटिव्स एसोसिएशन ऑफ एमटीएनएल टीईएएम और एमईवाई का संयुक्त फोरम है। एमटीएनएल के अधिकारियों का कहना है कि नवरत्न कंपनी होने के बावजूद इसका प्रबंधन सरकार द्वारा निर्धारित किए गए नए वेतनमान के 30 प्रतिशत फिटमैंट के स्थान पर पांच प्रशित फिटमैंट ही लागू कर रहा है। इसके साथ साथ मकान किराए भत्ते को भी दिसंबर 2006 के देय पर निर्धारित किया जा रहा है। प्रबंधन के इस निर्णय से अधिकारियों को सात से आठ हजार रूपए का नुकसान हो रहा है। टीईएएम के महासचिव एके कौशिक ने बताया कि प्रबंधन के निर्णय से एमटीएनएल के आठ हजार अधिकारी दिल्ली और मुंबई में प्रभावित हो रहे हैं। इससे पहले भी वह लोग अपनी शिकायत के बारे में सरकार और आला अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं। लेकिन सरकार की ओर से कोई पहल न होने की वजह से उन्हें प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

महामेधा
10-04-2009

एमटीएनएल अधिकारियों ने मांगों के लिए दिया धरना

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। एमटीएनएल के करीब आठ हजार अधिकारियों ने एमटीएनएल के कार्पोरेट ऑफिस जीवन भारती बिल्डिंग के सामने अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया। यह धरना पूरे दिन चला और ज्वाइंट फ्रंट के पदाधिकारियों ने बताया कि यदि एमटीएनएल प्रबंधन ने जल्दी ही सरकार द्वारा निर्धारित नए वेतनमान 30 प्रतिशत फिटमैंट के साथ लागू नहीं किए गए तो सभी अधिकारी 15 अप्रैल को प्रबंध निदेशक कार्यालय पर क्रमिक अनशन पर बैठेंगे।

इस संबंध में ये एमटीएनएल अधिकारी 23 मार्च से ही अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इन अधिकारियों का कहना है कि एमटीएनएल का प्रबंधन नवरत्न कंपनी होने के बावजूद सरकार द्वारा निर्धारित नए वेतनमान के 30 प्रतिशत फिटमैंट के बजाय 5 प्रतिशत फिटमैंट ही लागू कर रहा है।

साथ ही साथ इन अधिकारियों का यह भी मानना है कि प्रबंधन एक तरफ तो कर्मचारियों को नए वेतनमान नहीं दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ कमीशन खाने के लिए ऐसे नए-नए प्रोजेक्ट ला रहा है जिसका चार-पांच सालों से क्रियान्वयन ही नहीं हुआ है।